

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

f प्रश्न संख्या : 3310

13 , 2020 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

इ ो व्य स

3310. श्री ल

श्री वाई० देवेन्द्रप्पा:

क स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल के अनुसार देश म महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश म एड्स को व्याप्तता दूसरे स्थान पर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एड्स रोगियों को उच्च संख्या वाले आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कनाटक और तेलंगाना पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष प्रयास किए जा रहे ह; और

(घ) समाज म एड्स/एचआईवी ग्रस्त रोगियों के साथ भेदभाव नहीं हो और देखभाल एवं उपचार हेतु एचआईवी रोगियों का पता लगाना सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए ह?

त :

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन)

(क) और (ख) जी नहीं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019 के अनुसार आंध्र प्रदेश का 0.41 एचआईवी व्याप्ता के साथ 8वाँ स्थान रहा है तथा महाराष्ट्र का 0.26 एचआईवी व्याप्ता के साथ 17वां स्थान रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019 के अनुसार एचआईवी/ एड्स के राज्यवार आकड़े अनुलग्नक- I मे दिए गए ह।

(ग) भारत म एचआईवी/ एड्स को रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को कद्रीय क्षेत्र को एक योजना है, जिसम सभी राज्यों को तकनीकी, वित्तीय और वस्तुगत सहयोग प्रदान किया जाता है।

आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कनाटक और तेलंगाना मे उनको जनसंख्या और एचआईवी/ एड्स व्याप्ता को वजह से अधिक एचआईवी (पीएलएचआईवी) पीडित लोग रहते ह और इसलिए ये एचआईवी/ एड्स हेतु परीक्षण और संक्रमित व्यक्तियों के लिए निःशुल्क एंटी रेट्रो वायरल उपचार को व्यवस्था हेतु सुविधा कद्रों, मर्दों और जनशक्ति को संख्या के संदभ म आनुपातिक रुप से उच्चतर सहयोग

प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ महामारी विज्ञान को दृष्टि से यह इंगित किया जाता है कि वहाँ विशेष प्रयास अपेक्षित हैं, वहाँ एनएसीपी में व्यापक कारवाई शुरू की जाती है।

कायात्मक प्रयासों का राज्य वार व्यौरा अनुलग्नक- II और III पर दिया गया है।

(घ) सरकार एचआईवी/ एड्स पीड़ित लोगों के कंलक एवं भेदभाव के समाधान हेतु मास मीडिया, आउट- डोर तथा लोक मीडिया के माध्यम से 360 डिग्री मल्टीमीडिया अभियान चलाती है।

एचआईवी और एड्स (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 2017 रोजगार एवं व्यवसाय, स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं में अनुचित व्यवहार, शैक्षणिक संस्थाओं और सेवाओं में अनुचित व्यवहार के संबंध में किसी भी प्रकार के भेदभाव को भी निषेध करता है। अधिनियम में एचआईवी/ एड्स पीड़ित व्यक्ति के विरुद्ध किसी भेदभाव तथा गोपनीयता भंग के लिए भी दण्डात्मक प्रावधान है।

एचआईवी निदान के माध्यम से परिचर्या और उपचार हेतु रोगियों को ट्रेकिंग के लिए एक ऑनलाईन साफ्टवेयर प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध है।

ज / राज्य क्षेत्र वार ढ

क्र.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	व्याप्तता
1	॑	1.19
2		0.82
3		0.73
4	त्रि	0.56
5	॑	0.5
6	॑	0.47
7		0.44
8	ध प्र	0.41
9	॑	0.38
10	दिल्ली	0.38
11		0.38
12	॑	0.35
13	॑	0.29
14	॑	0.28
15		0.28
16	॑	0.27
17	ष्ट	0.26
18	उत्तर प्रदेश	0.22
19		0.18
20		0.16
21	॑	0.14
22	॑	0.13
23	॑	0.13
24	ध प्र	0.11
25		0.11
26	॑ प्र	0.09
27		0.08
28	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.06
29		0.05
30	॑ के	0.05
31	जम्मू और कश्मीर	0.02
32	रु प्र	0
33		0
34	॑	0
35	॑	0

केंद्रीय स्वास्थ्य

ब्यूरो, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय स्वास्थ्य

एचआईवी परामश और परीक्षण सेवाओं (HCTS) का विवरण

ज / ज क्षेत्र	संख्या *			
	वि स्क्रीनिंग			
ध प्र	102	228	1425	180
	3	473	2419	413
प्र	126	575	2597	1426
वि	102	807	1800	209
	58	179	671	129

* 2020

१ कद्रों १ ज

ज	१ कद्रों १ ख	१ कद्रों १ ख	१ कद्रों १ ख
आंध्र प्रदेश	40	118	23
महाराष्ट्र	72	194	45
१	55	174	31
	22	76	13
	65	313	36

* १ 2020